जिंदगी के रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी मंजिल मिली।
– अज्ञात

राम मंदिर का शिलान्यास

कोरोना के भीषण प्रकोप के बीच भी शिलान्यास का यह कार्यक्रम संपन्न होना बताता है कि सरकार मंदिर निर्माण को अपने अंतिम बिंदु तक ले जाने में किसी भी तरह का विघ्न नहीं आने देगी। देखना है, इसके लिए जरूरी लचीलापन यह धारा ईजाद कर पाती है या नहीं।

आरती शाह।

अयोध्या में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास सिर्फ मंदिर आंदोलन का उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचना भर नहीं है। इस आंदोलन का लक्ष्य भी मंदिर बनवाने तक सीमित नहीं था। यह लक्ष्य था देश की राजनीतिक मुख्यधारा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार के इर्दगिर्द संचालित करने का। इस बड़े सपने के संदर्भ में देखें तो खुद को एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में परिभाषित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक इकाई के तौर पर बीजेपी ने जो तीन बड़े लक्ष्य अपने सामने रखे थे, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण उनमें सिर्फ एक था। बाकी दो लक्ष्य थे समान आचार संहिता और अनुच्छेद 370 का खात्मा।

यह भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के राजनीतिक मुख्यधारा बन जाने का ही सबूत है कि एनडीए–2 के रूप में अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के एक–सवा साल के अंदर ही बीजेपी इन तीनों लक्ष्यों को साध लेने का दावा करने की स्थिति में आ गई है। कोरोना के भीषण प्रकोप के बीच भी शिलान्यास का यह कार्यक्रम संपन्न होना बताता है कि सरकार मंदिर निर्माण को अपने अंतिम बिंदु तक ले जाने में किसी भी तरह का विघ्न नहीं आने देगी।

शिलान्यास के लिए 5 अगस्त की तारीख तय करने की और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन एक वजह जगजाहिर है कि जम्मू–कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा साल भर पहले इसी तारीख को समाप्त किया गया था। एक बार में तीन तलाक कहने की कुप्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करके यह सरकार समान आचार संहिता की तरफ भी एक ठोस कदम आगे बढ़ा चुकी है।

कुल मिलाकर देखें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मजबूत जमीन तैयार करके सत्ता हासिल करने और फिर उसके इर्दगिर्द एक बड़ा सामाजिक मतैक्य निर्मित करने में बीजेपी दुनिया की अन्य समान धाराओं के मुकाबले कहीं ज्यादा सफल हुई है। इसकी शुरुआत 1979 में शिया बहुल ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति से मानी जाती है, जिसकी काट के रूप में सऊदी अरब में वहाबी उभार देखने को मिला। इसने दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी जद में लिया और इसके अगले कदम के रूप में अल कायदा और आइसिस जैसे संगठन उभर आए जिन्होंने राष्ट्र का चक्कर ही पीछे छोड़ दिया।

यूरोपीय देशों में, खासकर जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रैटिक यूनियन जैसे प्रयोग धीरे–धीरे अपनी धार्मिक पहचान छोड़ते गए और सरकार में आते–जाते रहने के बावजूद उनकी स्थिति अब देश की बाकी पार्टियों जैसी ही है।

इसके विपरीत भारत में इस धारा का प्रभाव राजनीति, फिल्म, मीडिया और तकनीक से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अजेंडा आगे बढ़ाने में किसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि अब इसके सामने कुछ चुनौतियां जरूर खड़ी हो रही हैं। उपेक्षित पहचानों की दावेदारी और केंद्र–राज्य टकराव आने वाले दिनों में इसकी परीक्षा ले सकते हैं।

आध्यात्मिक प्रक्रिया

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। आप अपना खुद का निजी स्वर्ग ही बना लेंगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ यह नहीं है कि आप वहम, मतिभ्रम के एक स्तर से निकल कर दूसरे स्तर पर पहुंच जायें। यह इसलिये है कि आप अपने सारे वहम, सारे मतिभ्रम बिलकुल ही छोड़ दें, पूर्ण रूप से त्याग दें और वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करें, जैसी वो है, क्योंकि ये सारे प्रयत्न सत्य के बारे में हैं।

सत्य का अर्थ है, जो अस्तित्व में है, न कि वह जो आप अपने मन में बना लेते हैं। हम अपने मन में भगवान या शैतान देख सकते हैं। दोनों का ही महत्त्व नहीं है। आप जो कुछ देखते हैं वह आपकी संस्कृति पर निर्भर करता है, और उन चीजों पर भी जिनका अनुभव आपको हुआ है। जब आप लोगों को देखते हैं तो उनमें भगवान को देखते हैं या शैतान को दृ ये इस पर निर्भर करता है कि आप आशावादी हैं या निराशावादी।

संपादकीय

घटता डिजिटल गैप

ऑनलाइन शिक्षा को मिल रही प्रमुख चुनौतियों में से एक डिजिटल–डिवाइड है। एनएसएसओ 2017–18 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 42 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 प्रतिशत परिवारों में ही इंटरनेट था। पर आईएमएआई का नवंबर–2019 का डेटा बताता है कि गांव में 22.7 करोड़ और शहर में 20.5 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। यह पहली बार है जब गांवों में इंटरनेट यूजर्स शहरों से ज्यादा हैं। इस इंटरनेट क्रांति का कारण भारत में इंटरनेट की दरें विश्व में सबसे कम होना है। भारत कुल 50.3 करोड़ एक्टिव यूजर्स के साथ विश्व का दूसरा सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता देश बन गया है। चीन 83 करोड़ यूजर्स के साथ प्रथम और अमेरिका 30 करोड़ यूजर्स के साथ तृतीय स्थान पर है। डेटा हमें यह भी बताता है कि भारत में (5–11) वर्ष के 7.1 करोड़ बच्चे भी परिवारजनों के उपकरण का उपयोग करके ऑनलाइन हो जाते हैं। इस प्रकार डिजिटल–गैप को तेजी से भरा जा रहा है। जाहिर है, ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में संभावनाएं अपार हैं। गूगल–केपीएमजी स्टडी (2017) ने भारत का एडटेक बाजार वर्ष 2021 तक लगभग 2 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान लगाया था। वर्तमान में बाईजूस (10.5 अरब डॉलर बाजार मूल्य) एक डेकाकॉर्न स्टार्टअप हो गया है। लगभग 4600 भारतीय स्टार्टअप कंपनियां एडटेक के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। बेंगलुरु बेस्ड इंटरनेशनल एडटेक स्टार्टअप क्विजिज के सबसे ज्यादा यूजर्स अमेरिकी मिडिल स्कूल के छात्र हैं और यह अमेरिका के 50: विद्यालयों में अपनी पहुंच रखता है। भारत समावेशी ऑनलाइन शिक्षा के लिए कृतसंकल्प और 'सबका साथ– सबका विकास' की भावना से ओतप्रोत है, साथ ही 'संकल्प से सिद्धि' की प्रेरणा से गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा के संकल्प को सिद्ध करने के लिए तत्पर भी है।

सर्वोच्च न्यायालय की इस बारे में की गई तल्ख टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है कि 'दुनिया के किसी भी देश में लोगों को मरने के लिए गैस चैंबर में नहीं उतारा जाता है।'

ऑनलाइन प्लैटफॉर्म

अमिताभ कांत, हर्षित मिश्रा।।

प्रत्येक आपदा में वरदान की संभावनाएं अंतर्निहित होती हैं। भारत अपार संभावनाओं से युक्त विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। कोविड–19 आपदा को संभावना में बदलने की भारत में न केवल क्षमता है बल्कि इस क्षेत्र में वह वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। कोविड–19 महामारी ने शिक्षा समेत हर क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाला है। यूनेस्को के अनुसार विश्व भर में लगभग 126 करोड़ विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई है जिसमें लगभग 30 करोड़ भारतीय विद्यार्थी भी शामिल हैं। भारत सरकार ने कोविड आपदा में ऑनलाइन–शिक्षा प्रणाली की संभावना को तलाशा है तथा सहकारी संघवाद का पालन करते हुए, राज्यों के साथ इस दिशा में पूरी लगन के साथ प्रयासरत है।

स्वयं पोर्टल, स्वयंप्रभा समूह के 32 चैनल, दीक्षा पोर्टल, ई–पाठशाला पोर्टल, विद्यादान पोर्टल, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (एनआरओईआर) पोर्टल, नेशनल ऐकडेमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) पोर्टल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) पोर्टल, वर्चुअल लैब्स पोर्टल, इग्नू के विभिन्न ज्ञान दर्शन चौनल

इत्यादि ऑनलाइन प्लैटफॉर्म इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। दीक्षा पोर्टल पर 1900 पुस्तकों के 88,000 ई–कंटेंट को क्यूआर–कोड से टैग कर अपलोड कर दिया गया है। नीति आयोग झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में शिक्षा के क्षेत्र में सिस्टेमिक ट्रांसफॉर्मेशन हेतु प्रॉजेक्ट–साथ का सफल क्रियान्वयन तीनों राज्य सरकारों के साथ कर रहा है। इसका विस्तार तीनों राज्यों के 2.3 करोड़ विद्यार्थियों, 2.3 लाख विद्यालयों और 4.5 लाख शिक्षकों तक है। प्रॉजेक्ट–साथ ने कोविड महामारी को देखते हुए तत्काल अपना रूपांतरण डिजी–साथ के रूप में कर लिया है, जिससे अध्यापन कार्य के अलावा ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य के अनुरूप ही 'प्रधानमंत्री ई–विद्या कार्यक्रम' की घोषणा की गई है। इसमें एक राष्ट्र–एक डिजिटल प्लैटफॉर्म और एक कक्षा–एक चौनल जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रखा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक, प्रत्येक कक्षा के लिए 'एक कक्षा–एक चौनल' प्रारंभ किया जाएगा। यह वैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अथवा स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा का टीवी, रेडियो आदि माध्यमों से प्रसारण डिजिटल–डिवाइड को दूर करेगा और समावेशी ऑनलाइन शिक्षा को दूरस्थ स्थलों तक सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कोविड आपदा में पर्याप्त संभावनाएं हैं। लगभग 7.5 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं तथा भारत में केवल 70,000 विदेशी छात्र ही शिक्षा हेतु आते हैं। इस कारण प्रतिवर्ष 18 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा का नुकसान भी होता है।

कोविड परिस्थितियों ने यह संभावना पैदा की है कि हम न केवल विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को देश में ही उचित अवसर प्रदान करें बल्कि विदेशों से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करने की क्षमता भी विकसित करें। इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के गुणवत्ता–स्तर को वैश्विक करना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी–2020 द्वारा विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान करना एक अच्छी रणनीति है।

अष्टयोग-5140

	6		3		2	5
	32	2	31		32	
2		5			7	
	27		26	1	39	6
	1	3			6	
7	33		32	7	38	
3		1		5		2

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5139 का हल

1	2	3	4	5	6	7
2	25	1	28	6	41	6
3	7	6	1	2	4	5
4	38	4	24	4	29	4
5	7	2	4	1	6	3
6	45	7	33	7	25	2
7	6	5	4	3	2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

काफी संशोधन कर कड़े प्रावधान किए

मोहन। कई–कई घरों में तो एक से अधिक सहायक काम करते थे। इस तरह के कामों में औरतों की भागीदारी तीन चौथाई थी। इस तरह जहां एक ओर मध्यवर्ग की औरतों के रोजगार बढ़े, वहीं दूसरी तरफ औरतों की घर–गृहस्थी की जिम्मेदारी गरीब स्त्रियों या पुरुषों ने संभाली। लेकिन कोरोना काल में जब से मध्यवर्ग की नौकरियां जा रही हैं, औरतों के रोजगार बड़ी संख्या में घट रहे हैं। ऐसे में घर में काम करने वाली सहायिकाओं की विदाई भी हो रही है। अब अपने आसपास ऐसे दृश्य कम दिखते हैं कि कोई ई–रिक्शा से उतर रही है, कोई साइकिल चलाती आ रही है, कोई तेज कदमों से किसी फ्लैट की तरफ जा रही है। कई महिलाएं कह रही हैं कि उनकी तीस से सत्तर प्रतिशत तक सैलरी कम हो गई है। पति की भी तनख्वाह आधी रह गई है। अपना घर ही नहीं चल रहा, तो काम वाली का घर कैसे चलाएं?